



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022021-225130
CG-DL-E-12022021-225130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/माघ 23, 1942

No. 52]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

मामला सं. एडी-एसएसआर-28/2020

विषय : रूस से 'पालीटेट्राफ्लोरोइथिलीन' के आयातों से संबंधित चौथी निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

फा. सं. 7/47/2020-डीजीटीआर.—मै. गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि. (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें रूस (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पालीटेट्राफ्लोरोइथिलीन' (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु या पीटीएफई भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच करने का अनुरोध किया गया है।

- आवेदक ने पाटन और क्षति के जारी रहने और तीव्र पाटन और क्षति की संभावना का आरोप लगाया है और निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) को जारी रखने का अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा मूल पाटनरोधी जाँच अधिसूचना सं. 21/1/98-डीजीएडी दिनांक 22 जनवरी, 1999 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 21/1/98-डीजीएडी दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 के माध्यम से रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए की गई सिफारिश के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना सीमाशुल्क अधिसूचना सं 141/99-सीमाशुल्क दिनांक 30 दिसंबर, 1999 के द्वारा अधिसूचित किया गया। प्राधिकारी ने पहली एसएसआर जाँच में अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं 110/2004-सीमाशुल्क दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के माध्यम से लगाया गया था। तत्पश्चात प्राधिकारी ने दूसरी एसएसआर जाँच में अधिसूचना सं. 15/30/2008-डीजीएडी दिनांक 26 फरवरी, 2010 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। इसे तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं 57/2010-सीमाशुल्क दिनांक 3 मई, 2010 के माध्यम से लगाया गया था। प्राधिकारी ने एक बार फिर अधिसूचना सं. 15/2/2015-डीजीएडी दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे सीमाशुल्क अधिसूचना सं 23/2016-सीमाशुल्क दिनांक 6 जून, 2016 के माध्यम से लगाया गया।
4. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के माध्यम से की गई मध्यावधि समीक्षा जाँच में मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करने की भी सिफारिश की है।
5. परिवर्चना रोधी जाँच का समापन अंतिम जाँच परिणाम सं 07/22/2020-डीजीटीआर दिनांक 27 जनवरी 2021 के माध्यम से हुआ और प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीटीएफई पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीटीएफई तक विस्तार करने की सिफारिश की। दोनों सिफारिशों वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'पालीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (जिसे पीटीएफई के रूप में भी जाना जाता है) है। विचाराधीन उत्पाद को अंतिम निर्णायक समीक्षा जाँच में अंतिम जाँच परिणाम सं. 15/02/2015-डीजीएडी दिनांक 12-4-2017 के माध्यम से निम्नानुसार परिभाषित किया गया :

9. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रखा गया है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती अंतिम जाँच परिणाम के समय विचार किया गया था:

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

"5. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पालीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (जिसे पीटीएफई के रूप में भी जाना जाता है) है। पीटीएफई को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जैसे मोल्लिंग ग्रेड, फाइन पाउडर जलीय विसर्जन और फिल्ड ग्रेडों के यौगिक ग्रेड। पूर्ववर्ती मामले और वर्तमान शुल्कों के दायरे में शामिल सभी ग्रेड वर्तमान समीक्षा के दायरे में शामिल हैं। पीटीएफई को उसकी रासायनिक निष्क्रियता, इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, नॉन-टाक्सिक, अज्वलनशील, रेडिएशन के प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण के कम स्तर और व्यापक आवर्ती रेंज में उत्कृष्ट विद्युतीय गुणों जैसी अद्वितीय विशेषताओं के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में प्राथमिक रूप से प्रयोग किया जाता है।"

7. यह दलील दी गई है कि इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा पहले की गई जाँचों में परिभाषित किया गया है।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, अपने समान अंतिम प्रयोग, उनकी तकनीकी

और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँच में यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु हैं। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का विस्तार करने की समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान और मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद समान हैं इसलिए यह प्रथम दृष्टया माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो पूरी क्षति अवधि में आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या आयातक से संबंधित हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।
10. उपयुक्त के मद्देनजर और आवश्यक जाँच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ङ. पाटन की संभावना

11. आवेदक ने दावा किया है कि रूस के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमतों के साक्ष्य या प्रकाशित स्रोतों से कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, रूस में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों के संबंध में किसी प्रकाशन के अभाव में और उत्पाद की कीमतों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण, आवेदन को रूस के घरेलू बाजार में कीमतों का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। इस प्रकार, रूस के घरेलू बाजार में पीटीएफई की वास्तविक सौदा-बिक्री कीमत के बारे में कोई तर्कसंगत, प्रामाणिक और सटीक सूचना प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकी। तदनुसार, आवेदक ने रूस में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ को जोड़कर किया है। इस स्तर पर इस दावे को उचित पाया गया है और सामान्य मूल्य पर तदनुसार विचार किया गया है।
12. निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर की गई है। मालभाड़ा, बीमा, एफओबी निर्यात कीमत, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय और कमीशन के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
13. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु को भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि पर्याप्त भी है।

च. क्षति की संभावना

14. आवेदक ने शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध आयातों की भारी मात्रा, पूरी क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती, लागत में गिरावट के बिना रूसी उत्पादक द्वारा कीमत में कमी, संबद्ध आयातों की पाटित और क्षतिकारी कीमत, बाजार में संबद्ध आयातों के ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव, परिवंचना के कारण शुल्कों का प्रभावहीन होना और शुल्कों में वृद्धि करने की परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर क्षति के जारी रहने की संभावना का दावा किया है। प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि (क) घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है और दिनांक 18 दिसंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों पर हाल में समाप्त हुई एमटीआर जाँच में शुल्कों को बढ़ाना आवश्यक है और (ख) रूस के उत्पादक शुल्कों की परिवंचना कर रहे हैं और इस प्रकार रूस के मूल की संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध हाल में समाप्त हुई परिवंचना रोधी जाँच में पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को 27 जनवरी 2021 की अधिसूचना के द्वारा कोरिया के रास्ते निर्यात के द्वारा समाप्त कर रहा है।

छ. निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. संबद्ध देश

16. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश रूस है।

झ. जाँच की अवधि

17. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2019 से 30 सितम्बर 2020 (18 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जाँच की अवधि शामिल होगी।
18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जाँच अवधि के रूप में 18 महीने की अवधि पर विचार करना उचित समझते हैं ताकि पूरे वित्तीय वर्ष का आकलन किया जा सके और इसमें सर्वाधिक वर्तमान अवधि अर्थात् अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 (6 महीने) भी शामिल हैं जिस तक सूचना उपलब्ध है।

ञ. प्रक्रिया

19. इस समीक्षा जाँच में रूस से पालीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने और उसे जारी रखने वाली अधिसूचना सं. 15/2/2015-डीजीएडी दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथा अपेक्षित रूप से पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
20. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg 11-dgtr@gov.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उक्त पैरा 19 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जाँच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ठ. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg_11-dgtr@gov.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को लिखित में भेजे जाने चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ण. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2021

Case No. AD-SSR-28/2020

Subject : Initiation of 4th sunset review investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene” from Russia.

F. No. 7/47/2020-DGTR.—M/s. Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene” (hereinafter referred to as ‘product under consideration’ or ‘PUC’ or ‘subject goods’ or ‘PTFE’) originating in or exported from Russia (hereinafter referred to as ‘subject country’).

2. The Applicant has alleged continued dumping & injury and likelihood of intensified dumping and injury and have requested for initiation of sunset review and continuation of the anti-dumping duty (ADD) imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. Background

3. The original anti-dumping investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 21/1/98-DGAD dated 22nd January, 1999. On the basis of recommendation made by the Authority, vide Notification No. 21/1/98-DGAD, dated 13th October, 1999 for definitive antidumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from Russia, the imposition of antidumping duty was notified vide Custom Notification No. 141/99-Customs, dated 30th December, 1999. The Authority in the 1st SSR investigations recommended vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated 07th October, 2004 for continuation of definitive antidumping duty, that was then imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 110/2004-Customs dated 18th November, 2004. The Authority then in the 2nd SSR investigation again recommended for continuation of definitive antidumping duty vide Notification No. 15/30/2008-DGAD dated 26th February, 2010. This was then imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 57/2010-Customs dated 03rd May, 2010. The Authority once again recommended continuation of duties vide Notification No. 15/2/2015-DGAD dated 12th April, 2016 which was vide Customs Notification No. 23/2016-Customs dated 06th June, 2016.
4. The Authority has also recommended modification of existing definitive antidumping duty in a mid-term review investigation vide Notification No. 7/10/2020-DGTR dated 18th December, 2020.

5. The Anti-circumvention investigation was concluded vide Final Finding No. 07/22/2020-DGTR dated 27th January 2021 and the Authority *inter alia* recommended extension existing anti-dumping duty on PTFE originating in or exported from Russia to PTFE originating in or exported from Korea RP. Both the recommendations under consideration of the Ministry of Finance.

B. Product under Consideration (PUC)

6. The product under consideration in the present investigation is “Polytetrafluoroethylene (also referred to as PTFE)”. The product under consideration defined in the last sunset review investigation vide Final Findings No. 15/02/2015-DGAD dated 12.04.2017 is as follows:

“9. The scope of the product under consideration is kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings:

Product under Consideration and Like Article

“5. The product under consideration in the present case is "Polytetrafluoroethylene (also referred to as PTFE) originating in or exported from Russia. PTFE is produced in various grades, such as molding grade, fine powder, aqueous dispersion and compound grades of filled grades. All grades that were included in the scope of the previous case and current duties are within the scope of the present review. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, nonflammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.”

7. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

C. Like Article

8. The Applicant has submitted that there is no known difference in the subject goods produced by the applicant domestic producers and those exported from the subject country. Both products are comparable in terms of technical characteristics, their similar end uses, their technical and commercial substitutability and tariff classification. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation are same, it is *prima facie* considered that the subject good produced by the Domestic Industry and the subject good imported from the subject country are “like article”.

D. Domestic Industry and Standing

9. The application has been filed by M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd. The Applicant has certified that they have not imported the subject goods from the subject country in the entire injury period nor are they related to any producer or importer of subject goods. As per evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article.
10. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules *supra*.

E. Likelihood of dumping

11. The Applicant has claimed that efforts were made to get evidence of price of the product concerned in the domestic market of Russia or any evidence of price from published sources. However, in absence of any publication providing prices of the product under consideration in Russia and the product prices not being publicly available, the applicant has not been able to get any evidence of price in the domestic markets of Russia. Thus, no reasonable, authentic and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of PTFE in the domestic markets of Russia. The Applicant accordingly determined normal value in Russia considering facts available with regard to cost of production, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The claim is found appropriate at this stage and thus normal value has been considered accordingly.

12. The export price has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for freight, insurance, FOB export price, port expenses, bank charges, inland freight expenses and commission. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export price claimed by the Applicant.
13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market. The dumping margin is not only above *de minimis* but also substantial.

F. Likelihood of Injury

14. Applicant has claimed likelihood of continuation of injury on the grounds of significant volume of subject imports despite existence of duties, positive price undercutting during the entire injury period, reduction of prices by Russian producer without decline in cost, dumped and injurious price of subject imports, suppressing/depressing effect of subject imports in the market, ineffectiveness of duties due to circumvention and change in circumstances warranting enhancement of duties. The Authority has concluded that (a) the domestic industry continues to suffer injury and the duties need to be enhanced in the recently concluded MTR investigation on imports of subject goods from Russia vide Notification dated 18th dec 2020 and (b) producers in Russia are circumventing the duties and thereby undermining the remedial effects of anti-dumping duties in the recently concluded anti circumvention investigation against imports of subject goods originating in Russia but being exported through Korea vide Notification dated 27th January 2021.

G. Initiation of Sunset Review Investigation

15. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant substantiating likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

H. Subject Country

16. The subject country for the present investigation is Russia.

I. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation (hereinafter also referred to as "POI") for the present investigation is 1st April 2019 to 30th September 2020 (18 Months). For assessment of injury to the Domestic Industry the Authority shall cover the periods 2016- 17, 2017-18, 2018-19 and the POI.
18. The Authority has considered it appropriate to consider 18 months as period of investigation, in order to assess one full financial year and also cover the most recent period for which the information was available i.e. from April 2020 to September, 2020 (6 months). Further, since trade and business were affected due to COVID pandemic during the six-month period from April 2020 to September 2020, it is appropriate to consider a longer period.

J. Procedure

19. The review investigation will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification No. 15/2/2015-DGAD dated 12th April, 2016 recommending and continuing imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Polytetrafluoroethylene from Russia. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.
20. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. Submission of Information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
22. The known exporters, Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email address adg11-dgtr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of Information on Confidential Basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

35. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-Cooperation

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority